



सबगुरु न्यूज़

(राष्ट्रीय द्विभाषीय पाइपलाइन)

मो.9887907277 Email ID sabgurunews@gmail.com Website <https://www.sabguru.com>

सम्पादक - विजय सिंह

वर्ष 1

अंक 19

अजमेर, सोमवार 25 मार्च 2024

मूल्य 5 रुपए

पृष्ठ-4

सम्पादकीय

बीजेपी भी सुन रही है... गढ़ की जर्जर दीवारों का अप्साना

अलविदा होती सर्वी और पारा चढ़ने के साथ लोकसभा चुनाव की रणभेरी गूंज उठी है। अजमेर जिले का राजनीतिक भौमसम भी करवट लेता नजर आ रहा है। सफेदपोश लबादा ओडे राजनीति के मेंढक टारने लगे हैं। कहने को तो यहाँ परंपरागत रूप से बीजेपी और कांग्रेस के गोटर्स के बीच जंग होती आई है पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बागियों की फैज और निर्वलियों के दम ने राजनीतिक पार्टियों की दिमागी घटी बजा दी है। अजमेर उत्तर, व्यावर, किशनगढ़, पुकर, मसूदा, भिनाय में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों ने भाजपा और कांग्रेस को बता दिया है कि वोट बटोरने में हम भी किसी से कम नहीं। लोकसभा चुनाव में बस यही वजह प्रमुख राजनीतिक दलों के नीति निर्धारकों की बीची का कारण बनी हुई है। बागी भले ही जीत ना पाएं पर अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की जीत में रोडा बन सकते हैं। मजबूरन नाराज नेताओं को पुछकरा जाने लगा है। भाजपा में तो बाकायदा बिन मुहूर्त घर वापसी की रस्म अदायगी हो रही है। पूँक पूँक कर कदम बढ़ाने की तर्ज पर प्रत्याशी खोज कर थोपे जा रहे हैं। दलबदलुओं की पौ बाहर है। पाला बदलने विचारधारा त्वाने का खेल परवान चढ़ चुका है। भाजपा देशभर में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पूरी राजनीति के साथ चुनावी समर में उत्तरने का दावा कर रही है। राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतने का खाब देखा जा रहा है। इस खाब को सच करने में अजमेर संसदीय सीट भी मानी जा रही है। होलिका दहन के दिन जारी हुई भाजपा की पांचवी लिस्ट में भागीरथ चौधरी ने एक बार पिर बाकी दावेदारों का धधा बताते हुए बाजी मार ली। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान संगठनात्मक स्तर पर हुए कार्यकर्ताओं के बंटवारे और बगावत का बिगुल पूँकने वालों की बेरुखी भाजपा के लिए आने वाले तूफान का संकेत है पक्क कहना गलत ना होगा कि सत्ता सुख भोग रहे अजमेर के नेताओं के इशार पर चलने वाले पार्टी के रथानीय संगठन की स्थिति उत्तर से प्राप्त आदेशों की अनुपालना तक सीमित होकर रह गई है। ऐसे में पार्टी विद द फिल्में का दावा करने वाली बीजेपी के लिए अजमेर सीट गलफांस बन सकती है। गत बार 4 लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को भले ही पिर मैदान में उतारा गया हो लेकिन हाल ही में विश्वनगढ़ से विधानसभा सीट पर वे बुरी तरह हार कर बेकड़ी करा चुके हैं। ऐसे में लगातार दूसरी बार संसद तक पहुंचने के लिए चुनावी वैतरणी को हिचकोले भरती नाव के भरोसे वे कैसे पाकर रहे देखना भी दिलचस्प होगा। भागीरथ के खेवनहार खुद अपनी नाव मझधार से बड़ी मुश्किल से निकालकर ला पाए थे। भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान अजमेर उत्तर में जीत हासिल करने वाले वासुदेव देवनानी को कांग्रेस से अधिक अपनी ही पार्टी से बागवत कर निर्दलीय ताल ठोकने वाले पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बड़ी चुनौती दी थी। लगातार जीत रहे देवनानी को चुनाव के दौरान सारस्वत ने घुटनों के बल ला दिया था। लंगड़ाकर चलने वाले सारस्वत ने बढ़ती उम्र वाले देवनानी को इतना दौड़ाया कि उहें हाँफन तक की पुरुषत ना लेने दी। जमा खर्च बराबर करने की आदत से मजबूर देवनानी संघर्षपूर्ण जीत और स्पीकर जैसे पावरपुल पद से नवाजे जाने के बाद मत्रियों की तरह आदेश देने की ताकत वाले रुआब की जगह निर्देश देने तक सीमित कर दिए गए। मंत्रियों के दरखात वाली चिडिया बैठे बिना उनके निर्देश बेमानी हैं। हाँए एक बात जल्द है कि चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा दर्द देने वाली बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले ज्ञान सारस्वत की अब तक घरवापसी नहीं हुई। इसे भी देवनानी की ताकत से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव में करीब 26 हजार मत हासिल करने के बाद भी सारस्वत की सकारात्मक चुप्पी और मोदी बगावर के साथ बहने के पीछे संघ का वदरहस्त माना जा रहा है। ऐसे में उनकी घरवापसी को देवनानी लंबे समय तक रोक पाएं ऐसा नहीं लगता। राजनीति के जानकारों की माने तो स्पीकर जैसे विधायिका के पद से नवाजे जाने के बाद देवनानी अब भाजपा के काम के नहीं रहे। वे चाहकर भी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में खुलकर प्रयावर नहीं कर सकते। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र का खेवनहार कौन बनेगा यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। जिला बन चुके व्यावर को भले ही राजसंदर्भ का परकोटा अपने आगोश में ले चुका हो लेकिन उसकी आत्मा अब भी अजमेर से जुड़ी हुई है। यहाँ विधानसभा चुनाव में एक अनार सी बीमार की तर्ज पर टिकट चाहने वालों की लंबी फेहरिस्त में शंकर सिंह रावत भले ही बाजी मार गए हों लेकिन निर्दलीय ताल ठोकने वाले इन्द्र सिंह बागावास जैसे सनातनियों ने रावत की जीत वोटों की गिनती हो जाने तक सांसद में डाले रखा। कृष्ण ऐसे हो सुरक्षा वापसी हो गई जो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ना उगलते बने ना निगलते बने सरीखा है। अभियान में भाजपा एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव में उत्तरी हो एसा नहीं है। तब की बनी गाँठे लोकसभा चुनाव में खुल जाएंगी इसको लेकर भाजपा आलाकमान भले ही अतिआत्मविभास में हो लेकिन धरातल पर इसके आसार फिलवक तक नजर नहीं आ रहे। अंत में बात भाजपा की संगठनात्मक एकजुटता की तो बतावें शहर और देहात के अध्यक्ष एक बड़े नेताओं के आगमन के इतर कभी एक जाजम पर बैठे नहीं दिखे। अजमेर उत्तर और दक्षिण में बटी शहर भाजपा के हाल जगहजिर है। देवनानी के वदरहस्त से पार्षद से शहर अध्यक्ष का ताज पहनने वाले रमेश सोनी भी सिर्फ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष से अधिक साख नहीं बना सकते हैं। उधर पूर्व में दाढ़ी होने का तमगा धारण करने के बाद देहात भाजपा अध्यक्ष देवीशकर भूताल की राजनीति आलाकमान के वदरहस्त तले चल रही है। देहात से चुने गए विधायक अपने दम पर राजनीतिक जमीन बचाए हुए हैं।

भाजपा ने जारी की 5वीं सूची, 17 राज्यों की 111 सीटों पर उम्मीदवार घोषित

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की पांचवीं सूची में 17 राज्यों की 111 सीटों पर अपने उम्मीदवार रविवार शाम घोषित कर दिए। पार्टी की ओर से जारी विज्ञित में बताया कि पार्टी की कंट्रीव चुनाव समिति ने इन नामों को स्वीकृति दी है। पांचवीं सूची में 111 उम्मीदवारों में से 20 महिलाएं शामिल हैं।

अजमेर से
भागीरथ चौधरी
को फिर
दिया मौका



बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर से अर्जुन सिंह को तथा ताम्बुलुक से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को टिकट दिया गया है जो हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे कर भाजपा में शामिल हुए हैं। राजस्थान में श्रीगंगानगर (सु) से प्रियका बालन, झुंझुनूं से शुभकरण चौधरी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेन्द्र सिंह, जयपुर से मंजू शर्मा, टॉक सवाई माधोपुर से सुखबीरी सिंह जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश में अराकू (सु) सीट से विधायक अराकू से आराकू से आनंद चाहने वाले वाले वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को भले ही पिर मैदान में उतारा गया हो लेकिन हाल ही में विश्वनगढ़ के द्वारा चुनावी घोषित किया गया।

बिहार में पश्चिम चंपारण से डॉ. संजय जयसवाल पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह मधुबनी से अशोक कुमार सिंह, देकनाल से रुद्रनारायण पाणी, बलांगीर से संगीता कुमारी सिंह देव, कालाहांडी से मालविका के शरीर देव, नवरागपुर (सु) से बलभद्र माझी केन्द्र पाड़ा से बैजयंत जय पांडा जगतसिंह पुर (सु) से विभू प्रसाद तराई, पुरी से डॉ. संवित पात्रा, भुवेश्वर से अपराजिता सारंगी अस्का से अनिता शुभदर्शनी ब्रह्मपुर से प्रदीप कुमार पाणिग्रही कोरापुर (सु) कालेराम माझी पार्टी प्रत्याशी होंगे। सिस्किम में दिनेश चन्द्र नेपालतेलंगाना में वारंगल (सु) से अरुरी रमेश और खम्मम से तन्द्रा विनाद राव पार्टी के उम्मीदवार होंगे।

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल, गाजियाबाद से अलीगढ़ से अनुष वालिम्की, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार पीलीभीत से जितिन प्रसाद सुल्तानपुर से मेनका गांधी कानुपर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी सु राजरानी रावत, बहराईय, सु डॉ अरविंद गौड़ पार्टी प्रत्याशी होंगे। पश्चिम बंगाल में जलपाइजुड़ी(सु) से डा. जयंत राय। दारिंगिंग से राजू बिष्ट रायगंज से कार्तिक पॉल, जंगीपुर से धनंजय घोष कृष्णानगर से राजमाता अमृता राय और बैलभद्र दत्त, बारासात से स्वन मजूमदार, बिल्लीरहट से रेखा पात्र

हिमाचल प्रदेश में बहुमत के लिए कांग्रेस को 1 व भाजपा को 10 विधायकों की जरूरत



भाजपा के पास 25 विधायक हैं। राज्य में नौ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। छह विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, सुजानपुर, गगरेट, कुटलैहड़, बड़सर और लाहौल-स्पीति में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। नालांगढ़, देहरा और हमीरपुर में भी एक जून 2024 को ही उपचुनाव की घोषणा जल्द होने के आसार हैं। उपचुनाव में अगर भाजपा ही सभी 9 सीटें जीतती हैं तो प्रदेश में पिछ से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए दोनों दलों को 35 विधायकों की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में सत्ता की खातिर आने वाले दिनों में हिमाचल में और सियासी घटनाक्रम होने के आसार बने हैं। बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के अलाव 34 विधायकों का संख्या बल जरूरी है। विधायकों की संख्या बराबर होने पर ही विधानसभा अध्यक्ष मतदान कर सकते हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 34 हैं। ऐसे में अगर बहुमत साबित करना पड़े तो कांग्रेस के 33 विधायक सदन में मतदान कर सकेंगे।

जून में होने विधानसभा के नौ उपचुनाव में अगर कांग्रेस सिर्फ़ एक सीट भी जीत जाती है तो उसके पास बहुमत साबित करने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। ऐसे में सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीती और भाजपा के प्रत्याशी ही नौ सीटों पर विजयी रहे तो भाजपा के विधायकों का आंकड़ा 25 से बढ़कर 34 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उधर अटकलें हैं कि आने वाले दिनों में 35 विधायकों के जाऊँ आंकड़े तक पहुंचने के लिए और उथल-पुथल हो सकती है। दोनों राजनीतिक दल एक-दूसरे के विधायकों को तोड़ने की फिराक में रहेंगे। विधायकों का संख्या बल अधिक होने पर अगर भाजपा सरकार बनाती है तो बहुमत साबित करने के समय उनकी स्थिति भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। सरकार के गठन के बाद भाजपा को अपना विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करना होगा। सदन में बहुमत साबित करते समय विधानसभा अध्यक्ष फिर वोट नहीं दे सकेंगे ऐसे में मतदान करने वाले भाजपा के विधायकों की संख्या घटकर 33 हो जाएगी। विधायकों के संख्या बल के अनुसार कांग्रेस के पास 34 का आंकड़ा रहेगा। इस स्थिति में प्रदेश में फिर सियासी संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में जिस भी राजनीतिक दल को प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनानी है उसे कम से कम 35 विधायकों की जरूरत रहेगी।

रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर सेन्टर रुल्स 1956 के अनुसार

‘सबग्रुह न्यूज’

समाचार पत्र के स्वामित्व व अन्य विवरण का ब्यौरा

प्रपत्र-4

(देखिये नियम-8)

1. प्रकाशन का स्थान - कार्यालय 6/12, बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड
कॉलोनी पंचशील अजमेर

2. प्रकाशन अवधि - पाक्षिक

3. मुद्रक का नाम - इंडिया ऑफसेट

क्या भारत का नागरिक है - हाँ

4. मुद्रणालय का नाम - किशन गुप्ता
419 ब्रह्मपुरी जयपुर रोड अजमेर

5. प्रकाशक का नाम - विजय सिंह

क्या भारत के नागरिक है - हाँ

पता - कार्यालय 6/12, बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड
कॉलोनी पंचशील अजमेर

6. सम्पादक का नाम - विजय सिंह

क्या भारत के नागरिक है - हाँ

पता - कार्यालय 6/12, बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड
कॉलोनी पंचशील अजमेर

7. उन सभी व्यक्तियों का नाम - विजय सिंह

व पते जो समाचार पत्र के कार्यालय 6/12, बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड
स्वामी हो तथा जो समस्त पूँजी कॉलोनी पंचशील अजमेर
के एक प्रतिशत से अधिक के (राज.)
साझेदार या हिस्सेदार हो कोई नहीं

मैं विजय सिंह एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे अधिकतम जानकारी
विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

टिक्की संख्या: 252-20001

दिनांक 25.3.2024

विजय सिंह
प्रकाशक के हस्ताक्षर

राजनाथ सिंह ने लेह में सैनिकों के साथ मनाई होली



नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लेह में सैनिकों के साथ रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और फायर एंड फ्यूरी कोर्स के जनरल ऑफिसर कमाडिंग लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली भी इस मौके पर उनके साथ थे। रक्षा मंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए दुर्गम इलाकों और प्रतिकूल मौसम में मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उनकी वीरता ए दृढ़ संकल्प और बलिदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों की सकारात्मक प्रतिबद्धता शून्य से भी कम तापामान से भी ऊपर सुनिवाली

कन तापनान स मा ज्यादा भजबूत होती है। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है मुंबई वित्तीय राजधानी है और बैंगलूरु प्रौद्योगिकी राजधानी है उसी तरह लद्दाख भारत की वीरता और बहादुरी की राजधानी है। सिंह ने कहा कि पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि हमारे बहादुर सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

हम प्रगति कर रहे हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं क्योंकि हमारे सतर्क सैनिक सीमाओं पर तैयार खड़े हैं। प्रत्येक नागरिक को सशस्त्र बलों पर गर्व है क्योंकि वे अपने परिवारों से बहुत दूर रहते हैं ताकि हम होली और अन्य त्योहार अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्वक मना सकें। राष्ट्र सदैव हमारे सैनिकों का छणी रहेगा और उनका साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

देश के रक्षकों के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से एक दिन पहले सैनिकों के साथ त्योहार मनाने की नई परंपरा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कारगिल की बर्फीली छोटियों पर राजस्थान के तपते मैदानों में और गहरे समुद्र में स्थित पनडुब्बियों में सैनिकों के साथ इस तरह का जश्न हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बनना चाहिए। इस अवसर पर राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही सैनिकों के साथ होली मनाने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना है कि त्योहारों को सबसे पहले ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में लेह के युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पूर्व वायु सेना प्रमुख आर के एस भदौरिया भाजपा में शामिल



नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना के पूर्व
अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल, सेवानिवृत्त,
राकेश कुमार सिंह भद्रैरिया और युवजन
श्रमिका रायथू, वाईएसआर कॉग्रेस पार्टी
के नेता वरप्रसाद राव वेलागापल्ली ने आज
यहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता
ग्रहण की। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे,
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं राष्ट्रीय
मीडिया सहप्रभारी डॉ. संजय मयूख ने उहें
भाजपा सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री
अनुराग ठाकुर ने एयर चीफ मार्शल राकेश
कुमार सिंह भद्रैरिया और वेलागापल्ली का
भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा
कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों से
प्रभावित होकर आज मोदी का परिवार और
भी बड़ा हो गया है।

टाकुर ने कहा कि पिछले चार दशकों से एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। देश के करोड़ों युवा सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तब वे मोदी की ओर बड़ी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ देखते हैं। उन्होंने कहा कि समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और 2047 तक विकसित भारत

का सपना केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है। संभव हो सकता है। भाजपा महासचिव तावडे ने एयर चीफ मार्शल, सेवानिवृत्त राकेश कुमार सिंह भद्रारिया और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वेलागापट्टी का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कई दलों के नेताओं ने भाजपा का सदस्यता ग्रहण की है।

भारतीय वायु सेना के पूर्व अध्यक्ष भद्रसिंहा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया है और कई पदक भी अर्जित किए हैं। तावड़े ने कहा कि वेलागापल्ली भी सक्रिय रूप से राजनीति में रहे हैं और काफी समय से जनता के बीच रहे हैं। तावड़े ने विश्वास जताया कि भाजपा में शामिल हुए दोनों लहर चल रही है। वह भी मोदी के कुशल नेतृत्व में देश के विकास कार्यों में योगदान देंगे। साथ ही नड्डा के मार्गदर्शन में मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का अवसर मिला है।

बहुजन समाज पार्टी ने 25 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार

;सु से सुरेन्द्र पाल सिंह मुरादाबाद से मो इरफन सौंपी रामपुर से जीशान खां संभल से शौलत अली अमरोहा से मुजाहिद हुसैन मेरठ से देववृत्त त्यागी बागपत से प्रवीण बंसल, गौतमबुद्ध नगर से राजेन्द्र सिंह सोलंकी बुलंदशहर ,सु से गिरीश चंद्र जाटव आंचला से आविद अली पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू और शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी सूची में प्रत्याशी के तौर पर हाथरस ,सु से हेमबाबू धनगर, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु, आगरा ,सुद्ध से पूजा अमरोही, फ़िरोहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा ए फिरोजाबाद से सरतेन्द्र जैन सोली, इटावा ;सु से सारिका सिंह बघेल, कानपुर से कलदीप भदौरिया अकबरपुर ;कानपुर से राजेश कुमार द्विवेदी और जालौन ,सुद्ध से सुरेश चंद्र गौतम का नाम शामिल किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को आठ सीटों पर मतदान होगा जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हो चुकी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर और नगीना, रामपुर और मुरादाबाद सीट में बसपा रोचक जंग में शामिल होगी। बसपा ने 2019 के आम चुनाव में सहारनपुर, बिजनौर और नगीना पर परचम पहराया था जबकि भाजपा के हिस्से में कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत और सपा के खाते में रामपुर और मुरादाबाद सीट आई थीं।

मजदूरों के मुद्दे! चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बनते



भारत में लोकतंत्र को 74 वर्ष पूरे हो गए हैं व आजादी का अमृत काल चल रहा हो फिर भी यह लोकतंत्र अधूरा सा लगता है क्योंकि लोकतंत्र के इस पार्टी तंत्र ने देश के एक बड़े हिस्से को एक दम से भूला दिया गया है। देश में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल 53.53 कामगारों में से 43.99 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में बड़ी संख्या में मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं यह प्रवास मौसमी व कुछ क्षेत्रों में लम्बा भी होता है। जो गांव शहर राज्य को छोड़कर रोजगार की तलाश में दूसरे शहर व राज्य में परिवार सहित व पुरुष चलें जाते हैं यह मजदूर अपने वर्तन वापस कब ए किन्तने समय में आएंगे पता नहीं। देश भौगोलिक रूप से भले ही आजाद हो गया हो लेकिन काम के कुछ क्षेत्रों में मजदूर आज भी अपना निर्णय के लिए खंतन नहीं होता है हालांकि मजदूर के जीवन के सारे निर्णय तो मालिक ही करता है। लोकतंत्र में हर पांच वर्ष में देश की सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े चुनाव लोकसभा, राज्यों के लिए विधानसभा व स्थानीय नगर निकाय व पंचायत राज के चुनाव होते हैं। लेकिन इस पंचवर्षीय चुनाव प्रणाली में पार्टी तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है चुनावों में राजनैतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाती है अच्छे प्रत्यासी का चयन एथन बल व घोषणा पत्र यह सब करती है ताकि अपने दल की सरकार बना सकें। बस सभी राजनैतिक दलों से एक चूक हो जाती है और वह जब भी राजनैतिक दल 100, 50 पत्रों का चुनावी घोषणा पत्र में देश की 40 प्रतिशत आबादी के लिए पांच लाइन की जगह भी नहीं मिलती है जब मजदूरों की बारी आती है तो या तो कागज कम पड़

जाता है या इनकी स्थानी सूख जाती है। कुछ दल तो मात्र एक लाइन में ही खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार देश की इन्हीं बड़ी आबादी को राजनैतिक दल क्यों बिसरा देते हैं।

क्यों इनके घोषणा पत्र मजदूरों के मुद्दे पर सूने हो जाते हैं? इसके क्या कारण हैं कि एक किताब जैसे घोषणा पत्र में थोड़ी भी जगह मजदूरों के लिए क्यों नहीं रख पाते हैं ऐसी क्या मजबूरी है क्या इसके लिए पूर्जीवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वाहक इसकी इजाजत नहीं देते या मजदूर लोकतंत्र व राजनैतिक दलों के लिए मजदूर कोई खास हैरिस्यत नहीं रखते या मजदूरों के कोई मुद्दे? मुद्दे ही नहीं है हाल ही में हमने कोविड जैसी महामारी में मजदूरों के हालात पूरे देश ने देखे हैं कैसे पूर्जी पतियों ने सभी मजदूरों को सङ्कट पर मरने के लिए छोड़ दिया था व खुद को अपने महल में रख्य व अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय रोजगार शोषण, न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मौलिक अधिकार व श्रम कानूनों की पालना जैसे सैकड़ों मुद्दे आज भी मुंह बाहें खड़े हैं लेकिन जब मजदूरों की बात आती है तो सबके सब क्यों चूपी साध लेते हैं। सब क्यों के मुद्दों पर बात होती है चुनावी मुद्दे भी बनते हैं सिर्फ मजदूरों पर ही बात क्यों नहीं होती है।

क्या सबके बोट का मूल्य अलग। अलग है:-देश के सविधान निर्माताओं ने

तो इस देश के नागरिकों को प्रत्येक नागरिक को एक बोट का अधिकार दिया था गरीब हो चाहे अमीर सबके बोट की कीमत बाबर होगी जब बोट की कीमत समान है तो बाकी मतदाताओं के हित व कल्याण के मुद्दों पर बात होती है राजनैतिक दल घोषणा पत्र में भी लम्बा चौड़ा लिखते हैं चुनावों में चर्चा भी होती है।

तो सिर्फ मजदूरों के मुद्दों पर ही बेरुखी क्यों:-असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूर जो स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिलने से एक जिले से दुसरे जिले में व एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में चले जाते हैं। इन मजदूरों को वापस अपने घर आने में महीनों सालों लग जाते हैं कहीं बार तो यह मजदूर अपने मताधिकार का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं कई बार मजदूर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहता भी है लेकिन वह अपने गांव व राज्य में जाने के लिए खंतन नहीं होता है।

बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मालिक मालिक बोट डालने के लिए भी छुट्टी नहीं देता है भले ही मतदान दिवस पर सर्वैतनिक अवकाश होता है लेकिन यह अवकाश आज तक मजदूरों को कभी मिला ही नहीं बहुत से कामों में तो छुट्टी ही नहीं मिलती व कुछ में मिलती है तो मजदूरी नहीं। देश में ऐसा ही एक व्यवसाय है इंट भट्टा इस पूरे व्यवसाय में सीजन भर के लिए नियमित मजदूर चाहिए होते हैं इस व्यवसाय में हर रोज नया मजदूर नहीं लाया

जा सकता है एवं देश में अधिकांश ईंट भट्टों पर प्रवासी मजदूर ही काम करते हैं इन मजदूरों को जब भी चुनाव होते हैं मालिकों

द्वारा घर नहीं जाने देने से भट्टों के सभी मजदूर बोट से वंचित रह जाते हैं। इसलिए भी राजनैतिक दल व स्थानीय जनप्रतिनिधि मजदूरों व उनके मुद्दों पर कम ध्यान देते हैं। इस्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर संगठनों की मजदूरत आवाज नहीं होने से भी मजदूर व मजदूरों के मुद्दे हाँशिंए पर रहे हैं। आज भी मजदूरों को दुर्दशा हम सब से छुपी नहीं है। मजदूरों की दुर्दशा नाम मजदूरी, बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य श्रम कानूनों की पालना, सुरक्षा के उपाय, सामाजिक सुरक्षा, सरकार की योजनाओं

से वंचित इन सबसे मजदूर कोषों दूर है सबसे ज्यादा दुर्दशा खराब है तो वह है मजदूर देश की सत्ता व राजनैतिक दलों पर पूर्णीपतियों का प्रभाव देखा जाता है इसलिए भी मजदूरों के मुद्दे हमेशा दोषम दर्जे के हो जाते हैं सबकी प्राथमिकता सिर्फ मालिक होते हैं। उत्तर प्रदेश के चिक्रुट जिले मजदूर सुरक्षा रेलास बताते हैं की मैं पिछले 25 सालों से राजस्थान के ईंट भट्टों पर काम कर रहा हूं मैंने अभी तक जीवन में 3-4 बार ही बोट डाला पाया हूं जब भी बोट पड़ते हैं तब मैं अक्षर काम की वजह से बाहर ही रहता हूं कभी कभी बोट पड़ते हैं तब मैं अक्षर काम की वजह से बाहर ही रहता हूं कभी कभी बोट डालता है इसलिए भी मजदूरों को जगह मिलेगी व चुनावों में भी चर्चा होगी।

जब देश में एक देश की व्यवस्था जैसी कल्पना की जा रही है तो देश का नागरिक चुनाव के समय कहीं भी गोजूद हो उससे उसी जगह पर मताधिकार का उपयोग कर सकें ऐसी व्यवस्था हो ताकि प्रवासी मजदूर भी मताधिकार का उपयोग कर सकें जिसे सरकारें ए राजनैतिक दल मजदूरों के मुद्दों का अकाल खत्म कर सकें।

लोग तो गांव से आने के बाद 9-10 महीने भीलवाडा राजस्थान के ईंट भट्टों पर काम करते हैं

कब चुनाव होते हैं पता ही नहीं चलता है। कभी कभी गांव के सरपंचों के चुनाव का पता चलता है बाकी चुनाव में तो अंतिम बार कब बोट डाला है याद ही नहीं है। मजदूरों से बात करने से पता चलता है की

क्यों मजदूरों के मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बनते हैं ज्यादातर मजदूर बोट ही नहीं डालते हैं बल्कि इनको बोट डालने ही जाने नहीं दिया जाता है इसलिए चुनावों में राजनैतिक दल व प्रत्यासी व जनप्रतिनिधि मजदूरों की चर्चा ही नहीं करते हैं तभी हम लोग देखते हैं देश में लोकतंत्र लागू होने के इतने वर्षों बाद भी शत प्रतिशत मतदान क्यों नहीं होता है अक्षर देखने में आता है की लोकसभा चुनाव या विधानसभा में अधिकतम 60 से 80 प्रतिशत मतदान ही हो पाता है।

हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश में हर चुनाव में 100 प्रतिशत मतदान हो कोई भी नागरिक किसी भी कारण से चाहे वो अपने गांव शहर, राज्य से बाहर रहता हो मताधिकार से वंचित नहीं रहे। जब सभी मजदूर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपने मुद्दों के प्रति भी मुख्य होंगे तभी राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में भी मजदूरों को जगह मिलेगी व चुनावों में भी चर्चा होगी।

As temperatures escalate, Union Health Ministry and NDMA Issue Joint-Advisory to States on measures to prevent Hospital Fires during Summer months

UTs underscoring the paramount importance of proactive measures in preventing such devastating incidents.



State Departments and State Disaster Management Authorities have been directed to work in close collaboration to ensure that all accredited hospitals within their jurisdiction take immediate action

on the following: Thorough Inspections: Conduct comprehensive fire safety audit / on-site inspections of all hospitals to assess fire safety compliance. Ensure that fire-fighting systems, including fire alarms, fire smoke detectors, fire extinguishers, fire hydrants, and fire lifts, are present and fully functional. Electrical Load Audits: Address the critical issue of insufficient electrical load capacity. Hospitals must regularly conduct electrical load audits, particularly when adding new equipment or converting spaces into ICUs. Any identified discrepancies must be promptly rectified.

Fire NOC Compliance: Hospitals must strictly adhere to regulatory requirements and obtain valid fire No-Objection Certificates (NOCs) from their respective state fire departments. Prioritize re-calibration of electrical loads in older buildings constructed before adopting fire safety norms.

A detailed set of instructions outlining the steps and measures to be undertaken by hospitals to ensure fire safety compliance have also been provided to Chief Secretaries of all States and UTs, recommending them to disseminate the information among all accredited hospitals.

झालावाड़ में डंपर से कुचलकर 5 लोगों की हत्या, दो आरोपी अरेस्ट



झालावाड़। राजस्थान में झालावाड़ जिले के मध्य प्रदेश से सटे भवानी मंडी क्षेत्र में 5 लोगों को आपसी विवाद के बाद डंपर से कुचलकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफतार कर लिया। जिनमें भी जानकारी के अनुसार भवानी मंडी क्षेत्र के पगारिया थाना की गांव पर्याप्त निवासी दो भाई धीरप सिंह और भरत सिंह शनिवार रात को गांव के पास एक ढाबे पर शराब पार्टी कर रहे थे तभी दो युवक डूंगर सिंह और रणजीत सिंह भी गांव के एक डूंपर से कुचलकर उनको मार दिया। डूंपर से कुचले जाने से दोनों आरोपियों की गांव पर्याप्त धीरप

